Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

कक्षा -12

अध्याय - 6

भारत के संदर्भ में नियोजन और सततपोषणीय विकास

भाग - 1

रामावतार यादव

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

नियोजन → भविष्य में निर्धारित उद्देश्य (परीक्षा) को प्राप्त करने के लिए वर्तमान सोच - समझकर रूपरेखा तैयार करना ⇒ नियोजन

भारत स्वतन्त्र → 15 Aug 1947

||

चुनौतियाँ → (1) गरीबी (2) बेरोजगारी (3) अशिक्षा (4) आवास की कमी (5) चिकित्सा व्यवस्था खराब

||

भारत सरकार

||

नियोजन

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

नियोजन

- **खण्डीय नियोजन**
  - = अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र में नियोजन
    - (1) शिक्षा (2) स्वास्थ्य (3) उद्योग
    - (4) कृषि
- **प्रादेशिक नियोजन**
  - → जनजातीय क्षेत्र
  - → पर्वतीय क्षेत्र

भारत नियोजन → रूस

आयोग → योजना आयोग

स्थापना → 15 मार्च 1950

→ कार्य → पंचवर्षीय योजनाओं लागू।

↳ रूस

योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 इसका निति आयोग।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

- नियोजन एक सोच-विचार कर सम्पन्न की जाने वाली प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गतिविधियों के क्रियान्वन को सम्मिलित किया जाता है।

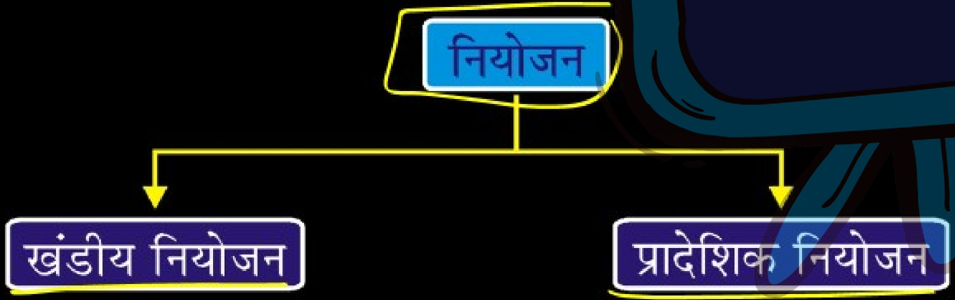

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- खण्डीय नियोजन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे- कृषि, सिचाई, ऊर्जा, विनिर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना एवं सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाकर उनको लागू किया जाता है।

खण्डीय नियोजन
↓
अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र
↓
संचार, परिवहन
उद्योग, सिंचाई

- प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत विकास के असमान प्रतिरूप से उत्पन्न प्रादेशिक असन्तुलन को कम करने के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाता है।

प्रादेशिक नियोजन
⇓
प्रादेशिक असन्तुलन को कम करने।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- भारत में केन्द्रीकृत नियोजन है और नियोजन का कार्य योजना आयोग को सौपा गया था। 15 मार्च 1950

- 1 जून 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। जनवरी

- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया है।

भारत नियोजन
॥
केन्द्रीकृत नियोजन

Under CSR Support by ipca Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

नीति आयोग

- → स्थापना – 1 Jan 2015
- → अध्यक्ष → प्रधानमंत्री
- → सदस्य → राज्यों C.m, केन्द्रीय मंत्री, केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक ।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

लक्ष्य क्षेत्र नियोजन :

- क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से 'लक्ष्य क्षेत्र' तथा 'लक्ष्य समूह' जैसे कार्यक्रमों को लागू किया गया था। जैसे- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि।
- 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तर - पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को तैयार किया गया।

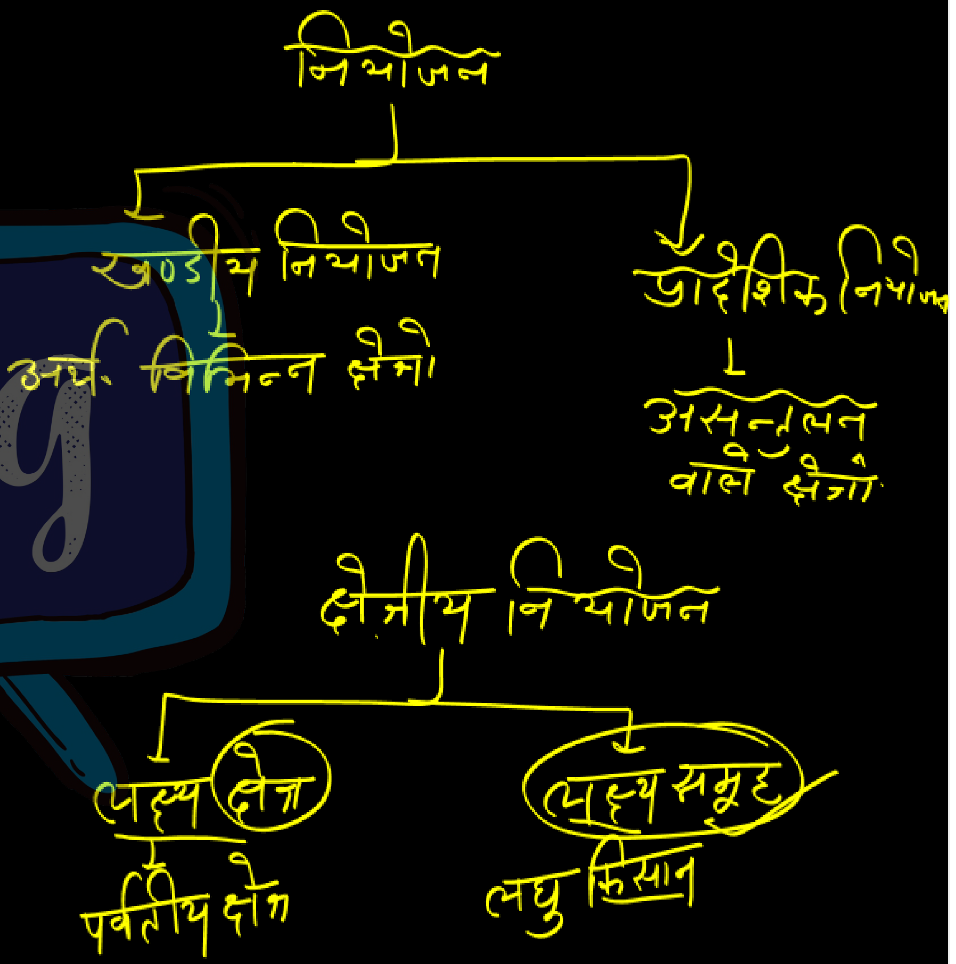

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

पंचवर्षीय योजना (रूस

पंचवर्षीय योजना	कार्यकाल
1	1951-56
2	1956-61
3	1961-66
योजना अवकाश	वार्षिक योजना - 3 1966-1969
4	1969-1974
5	1974-78
वार्षिक योजना -2	1978-80
6	1980-1985
7	1985-90
वार्षिक योजना -2	1990-92
(8)	1992-1997
(9)	1997-2002
(10)	2002-2007
(11)	2007-2012
(12)	2012-2017 (last)

51

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

चतुर्थ व पंचम पंचवर्षीय योजना की एक प्रमुख विशेषता प्रादेशिक/क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना रहा है। जैसे–

- पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- मरूस्थल विकास कार्यक्रम
- कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- नदी बेसिन विकास कार्यक्रम
- महानगरीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- द्वीप प्रदेशों का विकास कार्यक्रम

IV → 1969-1974

V → 1974-1978

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

1. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

- देश में 17% भू-भाग पहाड़ी क्षेत्र है तथा यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है।
- ऐसे क्षेत्र दो प्रकार के हैं।

(अ) वे जो सम्पूर्ण राज्य का निर्माण करते हैं। जैसे- पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख

(ब) वे जो किसी राज्य के भाग हैं। जैसे- असम के कार्बी आंगलौंग एवं उत्तरी कछार जिले पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जिला

इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा एवं केरल में पाया जाता है।

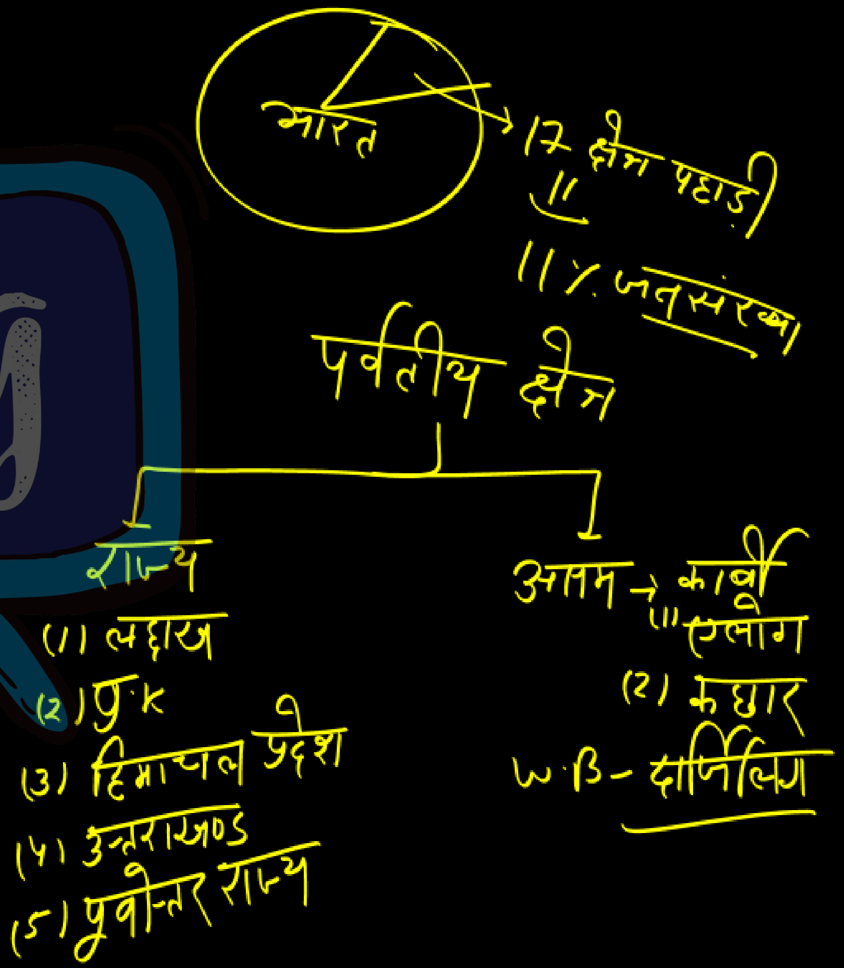

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

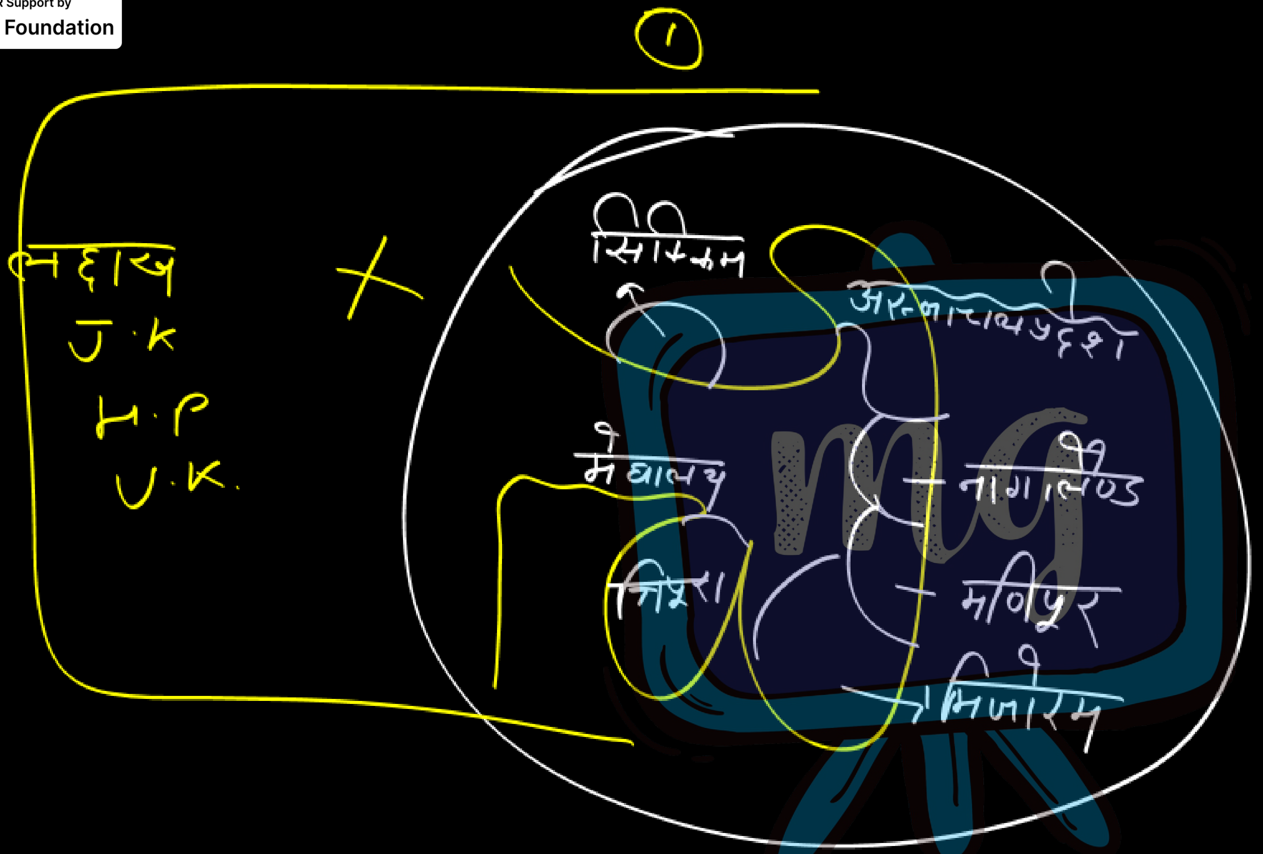

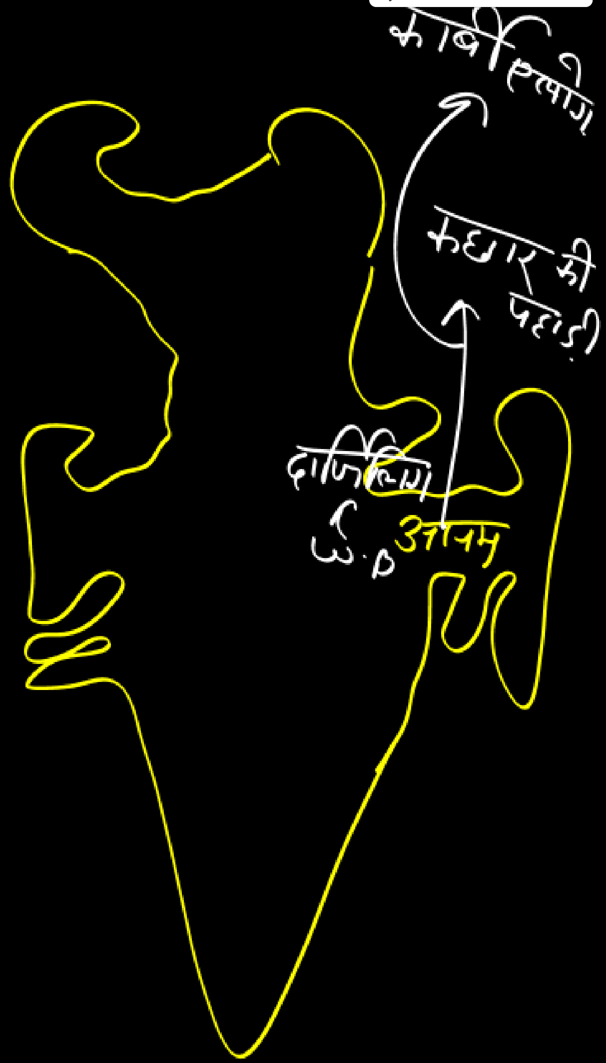

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

- 1981 में पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊँचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप-योजना लागू नहीं है।
- उक्त समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए निम्न सुझाव दिये-

1. सभी लोग लाभान्वित हों, केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही नहीं;
2. स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास;
3. जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेश-उन्मुखी बनाना;

1981 पिछड़े क्षेत्रों पर राष्ट्रीय समिति
⇓
सिफारिश
⇓
→ शामिल होने
① → समुद्र तल 600 मी. ऊँचाई
② जनजातीय उप-योजना में शामिल ना हो।

Under CSR Support by ipca | Foundation

missiongyan LET'S LEARN TOGETHER

4. अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो;
5. पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुँचाना;
6. पारिस्थिकीय संतुलन बनाए रखना।

पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याएँ मैदानी क्षेत्रों से भिन्न होती है यही कारण है कि इनकी स्थलाकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र हेतु अलग विकास योजनाओं को बनाने की आवश्यकता है